राहुल गांधी ने पत्रकार को दब्बू कहा तो इसमें गलत क्या है

मोदी राज में डरी हुई मीडिया को अपने गिरेबान में झांकना चाहिए

मजदूर मोर्चा ब्यूरो

नई दिल्ली: मोदी सरकार के बड़बोले मंत्री वी.के. सिंह ने पत्रकारों को वैश्या कहा तो पत्रकार जगत खामोश रहा। मोदी राज में डरा हुआ पूंजीवादी मीडिया और डर गया। लेकिन अभी जब कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी ने जब प्रधानमंत्री मोदी का इंटरव्यू लेने वाली पत्रकार स्मिता प्रकाश को दब्बू पत्रकार कहा तो तमाम पत्रकार और नेता बिलों से बाहर निकल आए और राहुल की आलोचना की झड़ी लगा दी।

जब आपने प्रेसीट्टयूट, न्यूज ट्रेडर, बाजारू, बिकाऊ, दलाल जैसी अपमानजनक उपाधियों को पहले ही एक सम्मान की तरह स्वीकार कर लिया था तो राहुल का पत्रकार को दब्बू कहने पर ही सारा स्वाभिमान क्या इसलिए नहीं उबल पड़ा है कि इस बार ताना विपक्ष के नेता ने मारा है? वह भी उन राहुल गांधी ने जो कल तक मीडिया में चुटकुलों और चकल्लस का विषय होते थे। हम सब उनको पप्पू कह रहे थे और लिख भी रहे थे।

यह सही है कि राहुल गांधी को अपनी सुधरती हुई छवि के बीच इस तरह की अभिव्यक्तियों से यथासंभव परहेज़ करना चाहिए लेकिन उनको यह कहने का मौका मिला क्यों, इस सवाल पर भी ईमानदारी से मीडिया मंचों पर चर्चा होनी चाहिए। कांग्रेस और राहुल गांधी की भर्त्सना ज़रूर करिए लेकिन मीडिया को फिलहाल अपने गिरेबान में भी झांक कर देखने की सख्त ज़रूरत है। हाल-फिलहाल में बीजेपी, केंद्र सरकार और राज्यों की बीजेपी सरकारों की चरण वंदना ने पिछले सभी रिकॉर्ड तोड दिए हैं। एएनआई की पत्रकार को राहुल का दब्बू कहना दरअसल मोदी राज में मीडिया का असली चेहरे की तरफ इशारा है। मीडिया को इस पॉजिटिव लेकर सरकार से तीखे सवाल करने चाहिए।

बीजेपी का नेता बीजेपी परस्त पत्रकार को, बीजेपी कवर करने वाले पत्रकार को और/या ऐसे पत्रकार को इंटरव्यू देना पसंद करता है जिसके साथ वह सहज महसूस करता है। यही हाल कांग्रेस और बाकी तमाम छोटी-बड़ी पार्टियों का है। किसी को अब तीखे सवाल पूछने वाले पत्रकार पसंद नहीं हैं। पत्रकार और मीडिया संस्थान भी नेताओं के साथ अपने संबंध बिगाड़ना नहीं चाहते। राजनीतिक इंटरव्यू भी अब चालू/चलताऊ किस्म की फिल्मी पत्रकारिता की तरह ज़्यादातर पीआर का हिस्सा हैं, इस सच से इन्कार नहीं किया जा सकता। नेताओं को मीडिया चाहिए, मीडिया को नेता। और अब इस रिश्ते में मिठास, नरमी, दोस्ती, दब्बूपन वगैरह खबरों के पुराने तौर-तरीकों से आगे जाकर बड़े-बड़े मीडिया समारोहों और इवेंट्स में नेताओं की भीड़ जुटाने के लिए ज़रूरी बन गई है।

अफसोस की बात यह है कि कुछ नामी-गिरामी लोगों की वजह पूरे मीडिया का दामन दागदार हो चुका है और आम लोगों की नज़रों में अब पत्रकारों के लिए पहले जैसा सम्मान नहीं रहा है। यह गंभीर समस्या है और इस पर खुल कर बेबाकी से बात होनी चाहिए।

अगर आप लोगों ने समाचार एजेंसी एएनआई की सीईओ और संपादक स्मिता प्रकाश का मोदी के साथ वह इंटरव्यू टीवी पर देखा हो या अखबारों में पढ़ा हो तो याद होगा कि कैसे सारे सवाल पहले से मोदी को पता थे। कुछ सवाल स्मिता प्रकाश खुद कर रही थीं और खुद ही जवाब भी दे रही थीं। पूरा इंटरव्यू देखने के बाद साफ-साफ नजर आता है कि यह प्रायोजित इंटरव्यू था। लेकिन पूंजीवादी मीडिया ने इस इंटरव्यू को इस तरह पेश किया कि जैसे मोदी ने पता नहीं क्या तीर मार लिया है। तमाम अखबारों को अप्रत्यक्ष निर्देश थे कि इस इंटरव्यू को अखबार के पहले पन्ने पर मुख्य खबर के रूप में छापा जाए। अखबारों ने नतमस्तक होकर अप्रत्यक्ष आदेश को स्वीकार किया।

राहुल ने उस पत्रकार को दब्बू कहने के अलावा और भी बहुत कुछ कहा था लेकिन मीडिया ने न उसे दिखाया और न छापा। राहुल ने संवाददाताओं से कहा, प्रधानमंत्री के पास आपके (मीडिया) सामने आने का साहस नहीं है। मैं यहां आता हूं। आप मुझसे कोई भी सवाल पूछ सकते हैं। मैं हर सात से 10 दिनों में यहां आता हूं। क्या आपने प्रधानमंत्री का इंटरव्यू देखा? स्मिता प्रकाश दब्बू (pliable) पत्रकार थीं। वह खुद सवाल भी कर रही थीं और जवाब भी दे रही थीं।"

राहुल गांधी की इस टिप्पणी पर स्मिता प्रकाश ने तीखी प्रतिक्रिया दी। प्रकाश ने ट्विट कर राहुल गांधी को जवाब देते हुए लिखा है कि प्रिय राहुल गांधी आपने मुझ पर हमला करने के लिए प्रेस कॉन्फेंस में सस्ता हथकंडा अपनाया। मैं सवाल पूछ रही थी, जवाब नहीं दे रही थी। आप श्री मोदी पर हमला करिए लेकिन मेरा उपहास उड़ाना बेतुका है। देश की सबसे पुरानी राजनीतिक पार्टी के अध्यक्ष से यह उम्मीद नहीं थी।

प्रकाश की टिप्पणी को लेकर भाजपा ने भी नाराजगी व्यक्त करते हुए राहुल गांधी से माफी की मांग की है। वहीं, केंद्रीय वित्त मंत्री जेटली ने ट्वीट करते हुए कहा कि आपातकाल की तानाशाह के पोते ने अपना असली डीएनए दिखा दिया है। उन्होंने एक स्वतंत्र संपादक को डराया और धमकी दी है। इसके अलावा उन्होंने एक और ट्वीट उन्होंने कहा, 'छद्म उदारवादी चुप क्यों हैं? एडिटर्स गिल्ड की प्रतिक्रिया का इंतजार है।'

देश के तमाम बड़े पत्रकारों ने भी ट्वीट कर स्मिता प्रकाश पर तंज सकने को लेकर कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी की आलोचना की है। लेकिन किसी ने मीडिया से यह सवाल नहीं किया कि आखिर राहुल गांधी की पूरी बात क्यों नहीं दिखाई गई और छापी गई। उनके बयान के एक हिस्से को लेकर पूरा मीडिया और नेता उनकी आलोचना में टूट पड़ा।

वक्त आ चुका है कि मीडिया और नेता दोनों अपने गिरेबान में झांके और सोचें कि राहुल या मोदी को ऐसा करने का मौका क्यों बार-बार मिल रहा है। क्या यह सच नहीं है कि मोदी में किसी भी प्रेस कॉन्फ्रेंस का सामना करने की हिम्मत नहीं है। मोदी के अपने पत्रकार हैं, जिनके साथ वो सेल्फी खिंचवाते हैं और पकौड़ा तलने को भी रोजगार बताते हैं और सारे पत्रकार तालियां बजाकर स्वागत करते हैं।

बहरहाल, प्रधानमंत्री के 95 मिनट के इस इंटरव्यू को वर्ष 2019 की पहली राजनीतिक फिल्म भी कह सकते हैं। जिसमें राहुल ने राफेल के मुद्दे पर तीखा हमला कर इस फिल्म को धो डाला है।

स्मार्ट सिटी का ड्रामा, न किसी को समझ है न इच्छा शक्ति

अवैध कब्जों, हरामखोरी व रिश्वतखोरी में है रुचि

फ़रीदाबाद (म.मो.) स्मार्ट सिटी के नाम पर अरबों रुपया खर्च होने के बाद उसका परिणाम जांचने के लिये यहां बार-बार सर्वेक्षण टीम आ रही हैं। इस सप्ताह भी एक टीम आई हुई है। जब भी यह टीम आती है तो मोटी रकम डकार चूके निगम अधिकारी सड़कों के किनारे सफ़ेद चूने की लकीरें सी खिंचवा कर निश्चिंत हो जाते हैं। उन्हें शायद लगता होगा कि इतने भर से शहर स्मार्ट हो जायेगा। सर्वेक्षण पर आने वाली टीमों को यह बात अच्छी तरह से समझ लेनी चाहिये कि यहां किसी की भी शहर को स्मार्ट बनाने में कतई नहीं है। सभी सम्बन्धित अधिकारियों व नेताओं का एक मात्र उद्देश्य केवल जनता को बेवकूफ़ बनाना और सरकारी पैसा डकारना है।

यदि ये लोग हरामखोरी व रिश्वतखोरी त्याग दें तो शहर तो अपने आप स्मार्ट व साफ़-सुथरा हो जायेगा। अपनी लूट-कमाई के लिये ये लोग धड़ाधड़ अवैध कब्जे व निर्माण कराने में जुटे हैं। यहां तक कि सभी बाजारों के फुटपाथ तक बेच खाये हैं, हर दुकान ने 10-10 फुट तक सड़क घेर रखी है। हर काम के लिये इन्हें मोटे पैसे चाहिये। हर ठेकेदार से मोटा कमीशन चाहिये, काम की गुणवत्ता से इनका कोई लेना-देना नहीं चाहे जितना मर्जी घटिया हो जाये।

वैसे तो शहर का कोई हिस्सा ऐसा नही जहां अवैध कब्ज़ों के चलते आम जनता परेशान न हो लेकिन एनएच-5 में तो अवैध कब्ज़ों ने कमाल ही कर रखा है। विदित है कि अवैध कब्जे बिना राजनेताओं व निगम अधिकारियों की मिली भगत के संभव नहीं हो सकते। नीलम चौक से रेलवे स्टेशन को जाने वाली मुख्य सड़क के दोनों ओर अनेकों लोगों ने सरकारी ज़मीन पर कब्ज़े कर रखे हैं। इनमें तीन-चार तो कबाड़ी हैं जिन्होंने अपने घर अथवा दुकान के सामने कबाड़ के ढेर लगा कर कब्ज़ा तो किया सो किया नगर की शक्ल भी बदसूरत कर रखी है। इन में से दो कबाड़ी भाईयों ने तो नाले की सरकारी ज़मीन पर कब्ज़ा करने के लिये नाले में ही मलबा भरवा दिया।

इसी तरह निगम पार्षद जसवंत सिंह के घर के पास सरकारी ज़मीन पर अमृत जल वाले ने बाकायदा अपना पलांट ही लगा रखा है। इसी तरह वहीं साथ में एक ने होटल बना कर कब्ज़ा कर लिया है। फ्रूट गार्डन व भगत सिंह कॉलोनी के कुछ लोगों का तो इन अवैध कब्ज़ों ने जीना तक दूभर कर दिया है क्योंकि उनके बरसाती पानी की बात तो छोड़िये, सीवरेज का सड़ा पानी तक नहीं निकल पा रहा है। लोगों को अपने घरों तक आने-जाने के लिये गंदे सीवेज में से होकर जाना पड़ता है। कुछ लोगों के तो घरों में भी यह सड़ा पानी घुसा हुआ है।

जाहिर है यह सब नगर निगम अधिकारियों की हरामखोरी व रिश्वतखोरी के चलते ही सम्भव है। परन्तु इससे भी बुरी बात तो यह है कि जनता के चुने हुए नुमायंदे पार्षद जसवंत सिंह व विधायक सीमा त्रिखा फ़िर किस मर्ज की दवा हैं? दरअसल ये दोनों ही नुमायंदे अवैध कब्जा धारकों के असली संरक्षक हैं। कब्ज़ा धारक निगम वालों को तो मोटा पैसा देते ही हैं साथ में इन चुने हुए प्रतिनिधियों का भी मुंह भरते हैं। इसके अलावा जानकार बताते हैं कि, पार्षद जसवंत सिंह के वार्ड में अनेकों, खासकर केसी रोड पर, अवैध निर्माण कार्य चल रहे हैं। इन सबसे उगाही के लिये पार्षद ने अपने बेटे के अलावा कई एजेंट भी छोड़ रखे हैं। इनमें सबसे मुख्य एजेंट है कटोरा जो अवैध बिल्डर एसोसिएशन का प्रधान भी है।

इंडियन हिस्ट्री कांग्रेस का 79 वां अधिवेशन मोदी सरकार की असहनशीलता का शिकार

जुगल किशोर गुप्ता

भारत की आज़ादी से पहले से स्थापित इंडियन हिस्ट्री कांग्रेस (आईएचसी) इतिहासकारों की प्रमुख व प्रतिष्ठित संस्था है जिसके अधिवेशन प्रतिवर्ष आयोजित किये जाते हैं जहां भारतीय व विदेशी इतिहासकार, इतिहास के शिक्षक व विद्यार्थी तथा इतिहास में रूचि रखने वाले व्यक्ति एकत्रित होते हैं और इतिहासकारों द्वारा प्रस्तुत शोध पत्रों पर विचार विमर्श करते हैं। अब तक इसके 78 अधिवेशन सफलतापूर्वक हो चुके हैं और 79 वां अधिवेशन का आयोजन सावित्री बाई फूले पूणे यूनिवर्सिटी (एसपीपीयू) तथा वहां के इतिहास विभाग के संयुक्त तत्वावधान में 28-30 दिसम्बर 2018 को करने का निर्णय किया गया था।

परन्तु एसपीपीयू के इतिहास विभाग के लोकल सेक्रेटरी के कार्यालय से 11 दिसम्बर 2018 के गुमनाम इमेल तथा एसपीपीयू के वेबसाईट से 12 दिसम्बर को सूचित किया गया कि आर्थिक कठिनाईयों व आवास व्यवस्था के अभाव के कारण आईएचसी का पूर्व निर्धारित अधिवेशन को स्थगित करने का एकतरफ़ा निर्णय लिया गया। आश्चर्य है कि एसपीपीयू के इतिहास विभाग के अध्यक्ष ने अधिवेशन रद्द करने की सूचना देने से पहले आईएचसी के सैक्रेटरी से इस मामले में बात करना भी आवश्यक नहीं समझा।

ध्यान देने योग्य है कि अधिवेशन में पूणे आने के लिये डेलिगेट्स ने अपना रिजर्वेशन लगभग तीन माह पूर्व करा लिया था और उन्होंने अपनी डेलिगेट्स फीस 1,000/-रुपये प्रति डेलिगेट के हिसाब से जमा भी करा दी थी जो कि वहां के इतिहास विभाग के अनुसार यह कुल राशि 15 लाख रुपया थी। यदि समय रहते अधिवेशन रद्द करने की सूचना आयोजकों द्वारा आईएचसी को दी जाती तो अन्य कोई विकल्प तलाशा जा सकता था। ऐन मौके पर रद्द करने की सूचना देना अधिवेशन का आयोजन न होने देने का मकसद था। आयोजन से केवल 15-16 दिन पहले आयोजकों द्वारा अचानक अपने हाथ खड़े कर देना आईएचसी के विरुद्ध एक राजनीतिक षडयंत्र प्रतीत होता है।

एसपीपीयू के इतिहास विभाग के कहना है कि जिन कार्पोरेट्स ने आर्थिक सहायता देने का वादा किया था वे पीछे हट गये तथा डेलिगेट्स के आवास के लिये वहां के जिस बासेवड़ी स्टेडियम के गेस्ट हाउस में प्रबन्ध किया था उन्होंने मौखिक रूप से सूचित किया कि ''खेलो इंडिया'' स्पोर्ट्स के कारण यह गेस्ट हाउस उपलब्ध नहीं होगा, हास्यासपद लगता है।

इस प्रकरण से कुछ प्रश्न खड़े होते हैं। अधिवेशन के वेन्यू का निर्णय दस माह पहले से हो गया था। यदि धन व आवस की उपलब्धता की कमी ही अधिवेशन को रद्द करने का वास्तविक कारण था तो इसकी सूचना आईएचसी को कुछ महीने पहले क्यों नहीं दी? डेलिगेट्स के लिये आवास की पूर्व निर्धारित व्यवस्था के रद्द होने से एसपीपीयू की आयोजन कुशलता व क्षमता पर प्रश्नचिन्ह लगता है कि क्या एसपीपीयू द्वारा इस तरह से प्रमुख अन्तर्राष्ट्रीय व राष्ट्रीय सम्मेलन आयोजित किये जाते हैं। राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ व इससे सम्बन्धित इतिहासकारों की संस्था इतिहास संकलन समिति तथा मोदी सरकार द्वारा इतिहास को तोड़-मरोड़कर संशोधित करने का प्रयास लगातार चल रहा है।

जादवपुर विश्वविद्यालय कलकत्ता में दिसम्बर 2017 में आयोजित आईएचसी के 78 वें अधिवेशन में पश्चिमी बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी, प्रख्यात इतिहासकार इरफ़ान हबीब, अधिवेशन के अध्यक्ष प्रोफ़ेसर के.एम. श्रीमाली तथा कई अन्य प्रख्यात इतिहासकारों ने मोदी सरकार के इतिहास को तोड़-मरोड़ कर प्रस्तुत करने के प्रयास की आलोचना की थी। मोदी सरकार व भाजपा को अपनी नीति की ओलोचना सहन नहीं हुई, जिसके परिणामस्वरूप उन्होंने 79 वें अधिवेशन को अपनी असहनशीलता की नीति का शिकार बना दिया।

FASHION.IN

Available all types of ladies cotton kurties, Fancy Kurties, Jegin, legin, Fancy Top,
T-Shirts, Trousers and imported material in wholesale

SPECIALITY IN FANCY TOP & FANCY KURTIES

लेडीज कपड़ों पर भारी छूट
एक बार सेवा का मौका अवश्य दें।

Address : 5M/22, N.I.T. FARIDABAD
NEAR DAYANAND WOMEN COLLEGE, ST. JOSEPH CONVENT SCHOOL ROAD . 9911489490

प्रकाशक, मुद्रक एवं संपादक सतीश कुमार ने अपने स्वामित्व में एजीएस पब्लिकेशन्स, डी-67, सैक्टर-6, नोएडा से मुद्रित करवा कर 1 डी/2बी.पी. नियर हार्डवेयर चौक, एनआईटी फरीदाबाद से प्रकाशित किया। Postal Reg. No. L/H.R/FBD/463-06